>

Title: Need to take steps to meet shortage of cement in the country .

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): सभापति महोदय, आज शून्यकाल के दौरान मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लोक हित के विषय को उठाना चाहता हूं। देश में सीमेंट की इन दिनों किल्लत जारी है। ...(व्यवधान) आज देश में हम सीमेंट की गुणवत्ता पर धीरे-धीरे नियंत्रण खोते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर यूपीए सरकार द्वारा अवसंरचना के निर्माण, इफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमैंट पर ध्यान दिया जा रहा है। ...(व्यवधान)

जहां ऐसे प्रौजेक्ट्स में सीमेंट की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर निजी मकानों को बनाने के लिए, बिजनेस आर्गनाइजेशन के लिए भी सीमेंट की आवश्यकता है। लेकिन सरकार के जितने उपक्रम और पब्लिक सैक्टर यूनिट्स थे, वे सारे के सारे बंद होने के कगार पर हैं या बंद हो चुके हैं। सरकार की ओर से मूल्य नियंत्रण,

* Not recorded

गुणवत्ता नियंत्रण या उत्पादन नियंत्रण के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं हैं। इसका नतीजा यह है कि प्राइवेट हाथों में पूरा का पूरा सीमेंट उद्योग चला गया है और कल ऐसी स्थिति आ सकती है कि कृत्रिम क्राइसिस क्रिएट करके सीमेंट के उत्पादन, मूल्य तथा उसकी गुणवत्ता पर नियंत्रण करने की कोशिश नॉन गवर्नमैंट, नॉन स्टेट की तरफ से की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में हम आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीमेंट उद्योग में गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन नियंत्रण एवं उसके मूल्य नियंत्रण के लिए एक अथॉरिटी बनायी जाये तथा सरकार की ओर से सीमेंट कार्पोरेशन को री-बैन किया जाये और उसे बेहतर बनाते हुए इस उद्योग को शुरू किया जाये ताकि वह किसी निजी हाथों में न आ सके।